



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 पौष 1933 (श0)  
(सं0 पटना 14) पटना, वृहस्पतिवार, 5 जनवरी 2012

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचनाएं  
04 जनवरी 2012

सं० वा०कर/टी०आर०यू०/2011-12/03-छाया-50—बिहार मूल्य वर्द्धित-कर नियमावली, 2005 के नियम 3 (A) के उप-नियम (9) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आयुक्त, वाणिज्य-कर के द्वारा निम्नांकित दिशा-निर्देश विनिर्दिष्ट किया जाता है :-

2 (क) निबंधन हेतु दाखिल आवेदन A-I अथवा A-IA यथास्थिति बिहार सरकार के अधिकृत वेबसाईट पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दाखिल किया जायेगा। आवेदन-पत्र सही एवं शुद्ध घोषणा-पत्र प्रपत्र D-I यदि आवश्यक हो के साथ दाखिल किया जायेगा।

(ख) आवेदक स्कैनड कॉपी में निम्न को भी दाखिल करेंगे :-

(I) आय-कर अधिनियम, 1961 के तहत निर्गत व्यवसायी का स्थायी लेखा संख्या कार्ड, और

(II) आवेदन में दिये गये व्यवसाय स्थल के पता से संबंधित साक्ष्य

**स्पष्टीकरण :-** यदि स्थायी लेखा संख्या व्यवसायी को नहीं आवंटित हो तो वैसी स्थिति में व्यवसाय के स्वत्वधारी या किसी फर्म के संदर्भ में उसके भागीदार का या व्यवसाय के स्थिति में अविभाज्य हिन्दु परिवार के मुखिया/कर्ता या निगम के संदर्भ में कंपनी अधिनियम, 1956 (1, 1956) या फिर किसी भी कानून के तहत अंगीभूत निगम के प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, किसी सोसाईटी, क्लब, एसोशियेशन, सरकार के विभाग या स्थानीय प्राधिकार की स्थिति में वहां का मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी अथवा प्रभारी पदाधिकारी।

(ग) आवेदन-पत्र के सिस्टम में अपलोड हो जाने के पश्चात् सिस्टम पावती आवेदक को निर्गत करेगा।

3. केन्द्रीयकृत निबंधन यूनिट के संबंध में निर्गत अधिसूचना के उप-नियम (1) के तहत प्राधिकृत पदाधिकारी अपलोडेड आवेदन के सभी कॉलमों की जाँच करने के पश्चात् कि वे पूर्णतया भरे पाये गये, आवेदक व्यवसायी को करदाता पहचान संख्या निर्गत करेगा।

4. यदि अपलोडेड आवेदन में कोई त्रुटि पायी गयी अथवा स्कैन डाक्यूमेन्ट अपूर्ण पाया जाता है तो प्राधिकृत पदाधिकारी त्रुटि रिपोर्ट जनित करेगा तथा यह आवेदनकर्ता को तत्क्षण ही इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचित किया जायेगा।

5. निर्गत निबंधन प्रमाण-पत्र की इलेक्ट्रॉनिक प्रति आवेदनकर्ता को उनके दिये गये ई-मेल पर संसूचित कर दी जायेगी तथा उसकी हार्ड कॉपी को व्यवसायी के द्वारा दिये गये पते पर निबंधित डाक/कुरियर अथवा स्पीड पोस्ट के द्वारा भेज दिया जायेगा।

उसकी एक प्रति इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संबंधित अंचल को जिसके क्षेत्राधिकार में व्यवसाय स्थल पड़ेगा, तीन दिनों के अन्दर भेज दिया जायेगा।

6. संबंधित अंचल प्रभारी एक महीने के भीतर आवेदन में प्रस्तुत की गयी विशिष्टियों का सत्यापन करेगा अथवा करवाएगा। इसके पश्चात् संबंधित अंचल प्रभारी उप-नियम (1) के अधीन निर्गत अधिसूचना में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को, जाँच-प्रतिवेदन प्राप्त होने के तीन दिनों के भीतर जाँच-प्रतिवेदन की एक प्रति अग्रसारित करेगा।

यदि जाँच प्रतिवेदन में कोई प्रतिकूल साक्ष्य अथवा विवरण जो निबंधन हेतु दाखिल आवेदन-पत्र से विपरीत पाया गया अथवा आवेदनकर्ता द्वारा किसी बात की जानकारी छिपाई गई या उसे गलत ढंग से बताया गया हो, तो वैसी परिस्थिति में उप-नियम (1) के अधीन प्राधिकृत पदाधिकारी व्यवसायी को अपना पक्ष रखने के लिए अवसर प्रदान करते हुए उप-नियम (4) में दिये गये उसके निबंधन प्रमाण-पत्र को रद्द करेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

राजित पुनहानी,

वाणिज्य-कर आयुक्त।

### *The 4th January 2012*

No. Bikri-Kar/TRU/2011-12/03-Shadow-50—In exercise of powers conferred under Sub Rule (9) of Rule 3A of the Bihar Value Added Tax Rules 2005, the Commissioner is pleased to specify the following procedure for dealing with registrations under rule 3A of the Bihar Value Added Tax Rules, 2005:

- 2(a) The application for registration in form A-1 or Form A-1A, as the case may be, shall be filed on the official website of the Commercial Taxes Department electronically. The application shall be accompanied by correct and complete declaration in Form D-1, if required.
- (b) The applicant shall also upload scanned copies of—
  - (i) The Permanent Account Number Card issued under the Income Tax Act, 1961; and
  - (ii) The proof of address of the place of business mentioned in the application for registration.

*Explanation—* In the event of a Permanent Account Number not being allotted to the applicant, a scanned copy of the Permanent Account Number allotted to the proprietor of the business; or in the case of a firm, of the partner authorized to act on behalf of the firm; or in the case of the business of an undivided Hindu family, of the Karta of the family; or in the case of a company incorporated under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) or a Corporation constituted under any law, of the managing director or the principal executive officer thereof; or in the case of a society, club or association of persons or a department of Government or local authority, of the principal executive officer, or of the officer-in-charge thereof, shall be uploaded.

- (c) Upon acknowledgment of the application, system generated receipt shall be granted by the system to the applicant.

3. The authority specified in the notification issued under sub-rule (1) shall, after verifying that the columns of the application have been duly filled in, generate a Tax Payer Identification Number (TIN) in respect of the applicant.

4. In case of any deficiency in the uploaded application form or in the scanned document the authority specified in the notification shall generate a deficiency report which shall be immediately communicated to the applicant electronically.

5. The electronic copy of the Registration Certificate shall be immediately communicated to the applicant on his given E-Mail. Signed copy of the Registration Certificate shall be sent to him by courier/speed-post/registered post as per the address given by him on application.

A copy of the same shall be forwarded electronically within a period of three days to the concerned circle under whose jurisdiction the dealer is registered.

6. The Circle in Charge shall after sending e-mail to the dealer whose C-I has been generated by the CRU, verify or caused to be verified the particulars furnished in the application within a month and shall forward a copy of the enquiry report to the authority specified in sub rule (1) within a period of three days of the receipt of the enquiry report;

If, in terms of the enquiry report the particulars furnished in the application are found to be incorrect, or the applicant has misrepresented or suppressed any fact, the authority under sub rule (1), shall, after giving the dealer an opportunity of being heard, cancel the certificate of registration granted under sub-rule (4).

By order of the Governor of Bihar,  
RAJIT PUNHANI,  
*Commissioner Commercial Taxes Department .*

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 14-571+500-डी0टी0पी0।  
**Website: <http://egazette.bih.nic.in>**